

इन्टीग्रेटेड एक्वा पार्क का निर्माण तेजी से करें पूर्ण: पुरूषोत्तम

एक्वापार्क में पंगेशियस व तिलापियां मछली की दो हैचरी, मछली प्रोसेसिंग यूनिट, ट्रेनिंग सेंटर के साथ ही प्रशासनिक ब्लॉक बनाये जायेंगे

सितारगंज (उद संवाददाता)। जनपद प्रभारी एवं सचिव पशुपालन, मत्स्य एवं डेरी विकास विभाग डॉ. बीबीआरसी पुरूषोत्तम ने अपने एक दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान विकास खण्ड सितारगंज के ग्राम प्रहलाद

एकड़ में 53.39 करोड़ की लागत से कार्यदायी संस्था सिंचाई प्रोजेक्ट देहरादून द्वारा बनाया जा रहा है। कार्यदायी संस्था के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि वर्षाकाल में जल भराव के कारण कार्य रूक गया था, लेकिन अब कार्य द्रुतगति

निर्देश मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार को मौके पर दिये। इसके उपरांत जनपद प्रभारी सचिव ने ग्राम पंचायत कल्याणपुर में आंगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया व महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित सामाग्री एपड,

योजना एवं यूएसजीसीएफ द्वारा वित्त पोषित श्रीमती राजवती व रंजीता देवी के बकरीबाड़ा का निरीक्षण किया व उनसे जानकारीयां ली। सचिव ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय बमनपुरी में मतदेय स्थल का निरीक्षण किया व बीएलओ

546 सदस्य जुड़े हैं। समिति का मुख्य उत्पादन मक्के का साइलेज, भूसा बनाया जाता है। समिति का वार्षिक टर्नओवर 1 करोड़ 70 लाख है जिसमें समिति का शुद्ध लाभ 15 लाख 20 हजार है। उन्होंने बताया कि समिति के प्रबन्ध कमेटी में 10

का जर्सी बैल सांड उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, उप जिलाधिकारी रविन्द्र जुआठा, खण्ड विकास अधिकारी सीआर आर्या, अपर निदेशक पशुपालन डॉ उमाशंकर, मुख्य



पलसिया, कल्याणपुर, बमनपुरी एवं ग्राम पंचायत बसगर शक्तिफार्म में राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के साथ ही मतदाता बुध का स्थलीय निरीक्षण किया। सचिव श्री पुरूषोत्तम ने ग्राम प्रहलाद पलसिया में मत्स्य विभाग का निर्माणधीन इन्टीग्रेटेड एक्वा पार्क का निरीक्षण किया। एक्वापार्क लगभग 40

से सभी कार्य एक साथ किये जायेंगे तथा 15 माह के भीतर पूर्ण कर लिए जायेंगे। उन्होंने बताया कि एक्वापार्क में पंगेशियस व तिलापियां मछली की दो हैचरी, मछली प्रोसेसिंग यूनिट, ट्रेनिंग सेंटर के साथ ही प्रशासनिक ब्लॉक बनाये जायेंगे। जिस पर सचिव ने एक्वा पार्क की साप्ताहिक कार्य प्रगति समीक्षा व मॉनिटरिंग करने के

किरिंग, मूंग घास की टोकरी, एलईडी बल्ब आदि सामाग्री का निरीक्षण किया व उनसे वार्ता की। उन्होंने कल्याणपुर गांव में संचालित देवभूमि जनसेवा केन्द्र सीएससी का भी निरीक्षण किया। इसके बाद सचिव श्री पुरूषोत्तम ने बमनपुरी के ग्राम चौमेला में गोदवैली योजना के अन्तर्गत संचालित एवं राज्य सैक्टर

मीना राणा व पुष्पावती से जानकारी ली व बीएलओ रजिस्टर समय से पूर्ण करने के निर्देश दिये। इसके पश्चात सचिव ने अधिकारियों के साथ ग्राम पंचायत बसगर, शक्तिफार्म में चारा उत्पादक सहकारी समिति का निरीक्षण किया। समिति के अध्यक्ष प्रभा रावत, सचिव उषा सरकार ने बताया कि इस समिति में

सदस्य है व सितम्बर माह तक समिति की 13 बैठके कर हो चुकी है। उन्होंने इस दौरान योगेन्द्र सिंह रावत संचालित गौशाला, डेरी व पिगरी फार्म का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये कहा सरकार द्वारा जो भी सहायता होगी अवश्य की जायेगी। योगेन्द्र उषा सरकार ने बताया कि इस समिति में

पशु चिकित्साधिकारी डॉ एसबी पाण्डे, अधीक्षण अभियंता सिंचाई परियोजना खण्ड देहरादून शरद श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता कमल सिंह, सहायक अभियंता राजीव सोनी, तहसीलदार पूजा शर्मा, वरिष्ठ मत्स्य निरीक्षण रविन्द्र कुमार, सहायक निवाचन अधिकारी आरएस अधिकारी आदि मौजूद थे।

तृतीय बाबा भक्त मण्डल रुद्रपुर के सौजन्य से

श्री बाला जी दरबार

एवं

श्याम संकीर्तन

29 सितम्बर 2024
निकट G मार्ट,
आदर्श कालोनी,
रुद्रपुर

मोना मेहता
स्वयंसेवा (हरिवाणर)

राजू बावरा
जयन्त (पु. वि.)

सम्पर्क सूत्र : 9837063083, 8218411123

बालिकाओं के लिए असुरक्षित स्थानों के चिन्हीकरण विषय पर कार्यशाला आयोजित

हल्द्वानी (उद संवाददाता)। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार संवेदीकरण कार्यशाला में गुरुवार को डीएवी सेंटनरी स्कूल में महिला एवम बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत "बालिकाओं द्वारा असुरक्षित स्थानों के चिन्हीकरण" विषय में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में जनपद के विभिन्न विभाग पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा एवम परिवीक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा बालिकाओं से उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। अपर निदेशक, प्रशिक्षण ऋचा सिंह ने बालिकाओं से वार्ता करते हुए ऐसे स्थानों के बारे में पूछा जहां पर वह असुरक्षित महसूस करती हैं। साथ ही बताया कि पिछली कार्यशालाओं में चिन्हित स्थानों पर समस्त संबंधित विभागों द्वारा कार्यवाही भी की जा रही है। बाल विकास परियोजना अधिकारी शिल्पा जोशी ने बालिकाओं को बिना डरे असुरक्षित स्थानों को चिन्हित करने के लिए कहा एवम बताया कि हल्द्वानी में इन कार्यशालाओं का असर देखने को मिल रहा है। बालिकाओं द्वारा हल्द्वानी में विभिन्न स्थानों को चिन्हित किया गया जैसे रिलायंस मॉल, कमलुआगांजा के पीछे आम का बगीचा, मेन मार्केट हल्द्वानी, डहरिया में इकोटाउज और पलैजियो के आसपास, हिम्मतपुर मल्ला,

हरिहरनगर, दयाल विहार, कुसुमखेड़ा, त्रिमूर्ति चौराहे के आसपास गलियों में, आरके टेंट हाउस रोड, जगदम्बा नगर आदि। बालिकाओं द्वारा बताया गया कि आम के बगीचे, रिलायंस मॉल के पीछे, कमलुआगांजा पर हर दिन ड्रग्स और शराब के नशे में लड़के झुंड बनाकर

काले शीशे की बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों में खड़े रहते हैं, कई बार मना करने पर भी नहीं सुनते, जिससे बालिकाओं को असुविधा होती है। कार्यशाला में बालिकाओं ने कुछ सुझाव भी पेश किए जैसे चिन्हित जगह पर लगातार पुलिस पेट्रोलिंग, गलियों में



बैठे रहते हैं और आते जाते लड़कियों से छेड़खानी करते हैं। यह बेहद संवेदनशील जगह है जहां पर अप्रिय घटना होने की संभावना है। कुछ चिन्हित स्थानों में ड्रग्स और शराब का कारोबार भी चलता है। सुनसान रास्ते में लड़के पीछे करते हैं, ऑटो वाले जानबूझकर सुनसान रास्ते से ले जाते हैं, अंधेरे का फायदा उठाकर लड़के बाइक से आकर गलत तरीके से छूते हैं और भेद कमेंट्स करते हैं। डीएवी स्कूल के प्राध्यापक ने बताया कि स्कूल के बाहर छुट्टी के समय अक्सर लड़के

स्ट्रीट लाइट, ऑटो चालक एवम ई-रिक्शा चालक का सत्यापन, ऑटो या रिक्शा स्टैंड पर एवम अन्य चिन्हित स्थानों पर गश्त आदि। इस कार्यशाला में चिन्हित स्थानों एवम कारणों के साथ समिति अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगी जिससे संबंधित विभाग को कार्यवाई के लिए निर्देशित किया जाएगा। कार्यक्रम में जिला प्रोबेशन कार्यालय से तबस्सुम ने हेलपलाइन नम्बर के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में विद्यालय की बालिकायें, प्रधानाचार्य एवम शिक्षिकायें, सुपरवाइजर उपस्थित थे।

चोरों ने एक और बाइक पर किया हाथ साफ

रुद्रपुर। बाइक चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। फुलसुंगा क्षेत्र में वाहन चोरों ने एक और बाइक पर हाथ साफ कर लिया। ग्राम घोसियाना जिला लखीमपुर खीरी निवासी दीप सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसने अपनी हीरो स्लैंडर बाइक संख्या यूपी 22एपी 6283 नई बस्ती फुलसुंगा में एक मकान के बाहर खड़ी की थी। करीब दो घंटे बाद जब वह वापस लौटा तो बाइक गायब थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर बाइक की तलाश शुरू कर दी है।

Guru Maa Advanced Dental Care

गुरु माँ एडवांस्ड डेन्टल क्लीनिक

WORLD-CLASS DENTAL CARE NOW IN YOUR CITY

रूट कैनाल विशेषज्ञ | डेन्टल इम्प्लांट | टेढ़े-मेढ़े दांतों का इलाज

डॉ. ऑचल क्षीगारा
बी.डी.एस., एम.डी.एस., एंडोडॉन्टिस्ट
रूट कैनाल स्पेशलिस्ट, कॉस्मेटिक डेन्टिस्ट
सर्टिफाइड एस्थेटिक डेन्टिस्ट

Guru Maa Advanced Dental Care "A Multi Speciality Dental Clinic"
१ प्लॉट नं 1, सिविल लाइन्स, रुद्रपुर | 7452880018, 05944-245666

उत्तरांचल दर्पण

सम्पादकीय सत्यम् शिवम् सुन्दरम्



जम्मू कश्मीर के मतदाता

जम्मू-कश्मीर में इस बार जब लोकसभा चुनावों के दौरान मतदान में वहां के लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था, तभी इस बात के संकेत मिल गए थे कि राज्य में राजनीति की तस्वीर तेजी से बदल रही है। अब विधानसभा चुनाव के पहले चरण में चौबीस सीटों के लिए हुए मतदान में जिस तरह वहां 61.13 फीसद वोटिंग का आंकड़ा आया, उससे साफ है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों का भरोसा अब देश के लोकतंत्र में मजबूत हो रहा है और उसे ज्यादा ताकत देने के लिए वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। राज्य में पिछले कुछ समय से लगातार आतंकवादी गतिविधियों के बीच जिस तरह की अप्रिय घटनाएं सामने आती रहीं, उससे इस बात की आशांका जरूर बनी हुई थी कि क्या इसका असर आम लोगों के चुनावों में हिस्सा लेने पर पड़ेगा और मतदान का फीसद कम रह सकता है, मगर इस डर को धता बताते हुए राज्य के लोगों ने अपना यह स्पष्ट कर दिया कि वे अब वहां लोकतंत्र और राजनीतिक प्रक्रिया को मजबूत करने को लेकर गंभीर हैं। आए दिन होने वाले आतंकी हमलों के जरिए आतंकवादी संगठन यह संदेश देने की कोशिश करते रहते हैं कि राज्य में अस्थिरता और हिंसा के बीच लोगों को चुनाव प्रक्रिया से दूर रहना चाहिए। अतीत में इस तरह की कोशिशों को कुछ कामयाबी मिली थी जब चुनाव में कभी मतदान का फीसद बेहद कम रहा था। मगर मौजूदा समय में राज्य में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जो भी राजनीतिक प्रक्रिया चलाई जा रही है, उसमें वहां की जनता की सकासमक प्रतिक्रिया उम्मीद जगाती है। दरअसल, राज्य में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद यह आशांका जताई जा रही थी कि वहां की जनता का रख चुनावों में मतदान के समय शायद सकासमक न रहे। सही है कि राज्य में अब भी आबादी के कुछ हिस्सों में इस मसले पर अलग-अलग विचार और असंतोष का भाव रहा है। बल्कि यह चुनावी मुद्दा भी बना और यह माना जा सकता है कि इस सवाल ने भी लोगों को चुनाव में हिस्सा लेने और अपनी राय जाहिर करने के लिए प्रेरक शक्ति का काम किया होगा। यह बेवजह नहीं है कि न केवल मतदान केंद्रों पर लोग उम्मीद से ज्यादा संख्या में उमड़ कर आए, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाला। एक समय था जब चुनाव की घोषणा के बाद आतंकवादी संगठनों की ओर से मतदान का बहिष्कार करने के लिए तरह-तरह की धमकियां दी जाती थीं। इस बार भी एक ओर राज्य में चुनाव आयोजित कराने की तैयारी चल रही थी और दूसरी ओर लगातार आतंकवादी संगठनों की ओर से कहीं सीमा पर घुसपैठ का प्रयास किया जा रहा था, कहीं लक्षित हमलों में हत्याएं की जा रही थीं, तो कभी सुरक्षा बलों के शिविरों पर हमले किए जा रहे थे। ऐसा करके आम जनता के बीच आखिर क्या संदेश देने की कोशिश की गई? मगर इस तरह की आतंकी हिंसा का जवाब जम्मू-कश्मीर के लोगों ने शांतिपूर्ण और उत्साहजनक मतदान करके दिया। इस लिहाज से देखें तो पहले लोकसभा, और फिर अब विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान में लंबी कतारें यह बताने के लिए काफी रहीं कि लोग अब वहां लंबे दौर के अशांत माहौल और आतंकवादी गतिविधियों से छुटकारा चाहते हैं और यह अंतिम तौर पर वहां लोकतंत्र की बहाली के जरिए ही संभव है। चुनाव में मतदान में बढ़-चढ़ कर हिस्सेदारी वहां के लोगों के भीतर भारतीय लोकतंत्र में बढ़ते भरोसे का सूचक है।

विधायक सुमित ने लगाया विकास कार्यों में उपेक्षा करने का आरोप

हल्द्वानी (उद संवाददाता)। हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार अनदेखी और भेदभाव किया जा रहा है। विधायक सुमित हृदयेश ने जिला प्रशासन पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने खनन न्यास निधि से कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों के प्रस्ताव डीएम कार्यालय को भेजे थे, लेकिन अब तक उन पर कोई स्वीकृति नहीं मिली है। प्रशासन का यह रवैया हल्द्वानी के विकास में जानबूझकर

अवरोध पैदा करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में तोड़-फोड़ तो लगातार की जा रही है, लेकिन हमारी जो बड़ी और महत्वपूर्ण योजनाएं थीं, उन्हें रोक दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि हल्द्वानी के विकास को जानबूझकर पीछे धकेला जा रहा है। सुमित ने कहा वह इस मुद्दे को सदन में मजबूती से उठाएंगे और जनता के अधि कारों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। हल्द्वानी के विकास को इस तरह अवरुद्ध करना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

रोडवेज बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

काशीपुर (उद संवाददाता)। यात्रियों के बस से नीचे उतरते वक्त रोडवेज बस चालक ने लापरवाही से बस चलाकर एक व्यक्ति को बुरी तरह जखमी कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रोडवेज बस चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। घटना के बारे में पुलिस को तहरीर देकर वार्ड नंबर 13 मोहल्ला छीपियान जसपुर निवासी अनिल कुमार पुत्र नन्दे सिंह ने बताया कि बीते 8 सितंबर को काशीपुर के कटोरताल चौकी क्षेत्र स्थित चामुंडा चौराहे के समीप रोडवेज बस संख्या यूपी 78 एचटी/8565 के चालक दादरी जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश निवासी भूषण त्यागी पुत्र ईश्वर चंद्र ने बस से उतरते वक्त अचानक तेजी और लापरवाही से बस चला दिया जिससे शिकायतकर्ता का भाई दरवाजे में अटक कर काफी दूर तक घिसाटता चला गया। दुर्घटना में उसे गंभीर चोटें आईं। इस मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी रोडवेज बस चालक के खिलाफ संबंधी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

2029 में एक देश, एक चुनाव!

एक देश, एक चुनाव, यानी देश में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ निकाय व पंचायत चुनाव भी एक साथ कराने की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के सौ दिन पूरे होने पर गृहमंत्री अमित शाह ने आत्मविश्वास के साथ कहा है कि 2029 के पहले एक साथ चुनाव का प्रबंध कर दिया जाएगा। साफ है, सरकार अपने इस महत्वाकांक्षी वादे को क्रियान्वित करने के प्रति संकल्पबद्ध है। इसी क्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट की अनुशंसाओं को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। साफ है, केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि सरकार अपने अजेंडे पर आगे बढ़ती रहेगी। उम्मीद है कि शीतकालीन सत्र में एक देश एक चुनाव कराने के नजरिए से शीतकालीन सत्र में इस विधेयक और इस प्रक्रिया को पूरी करने वाले संशोधन विधेयकों को पारित कराने की शुरुआत संसद में हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस समेत करीब 15 राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि भाजपा समेत 32 राजनीतिक दल इसके समर्थन में हैं। एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो इस समय जिन राज्य सरकारों का कार्यकाल बचा होगा, वह लोकसभा चुनाव तक ही पूरा मान लिया जाएगा। वैसे भी आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते रहे हैं, लेकिन 1968 और 1969 में समय के पहले ही कुछ राज्य सरकारें भंग कर दिए जाने से यह परंपरा टूट गई। अब इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान में करीब 18 संशोधन करने होंगे। इनमें से कुछ बदलावों के लिए राज्यों की भी अनुमति जरूरी होगी। यदि स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव भी साथ साथ होते हैं तो फिर मतदाता सूची तैयार निर्वाचन आयोग कराएगा। इस हेतु अनुच्छेद 325 में परिवर्तन करना होगा। साथ ही अनुच्छेद 324 ए में संशोधन करते हुए निगमों और पंचायतों के चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ करा लिए जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 368 ए के तहत इस संशोधन विधेयक को आधे राज्यों से भी पास करना जरूरी होगा। इसी अनुरूप केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी अलग से संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। इस रिपोर्ट से पहले संसदीय समिति भी देश में एक साथ चुनाव कराने की वकालत कर

चुकी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यदि लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ होते हैं तो लंबी चुनाव प्रक्रिया के चलते मतदाता में जो उदासीनता छा जाती है, वह दूर होगी। एक साथ चुनाव में वोट डालने के लिए मतदाता को एक ही बार घर से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचना होगा, अतएव मतदान का प्रतिशत बढ़ जाएगा। यदि यह स्थिति बनती है तो चुनाव में सरकारी धन कम खर्च होगा। 2019 के आम चुनाव में करीब 60,000 करोड़ खर्च हुए थे और 2024 के चुनाव में लगभग एक लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। एक साथ चुनाव में राजनीतिक दल और प्रत्याशी को भी कम धन खर्च करना होगा। दरअसल अलग-अलग चुनाव होने पर हारने वाले कई प्रत्याशी एक बार फिर किस्मत आजमाने के मूड में आ जाते हैं, वहीं विधायकों को भी लोकसभा और सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो सीट खाली होती है, उसे फिर से छह माह के भीतर भरने की संवैधानिक बाध्यता के चलते चुनाव कराना पड़ता है। नतीजतन जनता के साथ-साथ प्रत्याशी को भी चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी उदासीनता झेलनी पड़ती है। इस कारण सरकारी मशीनरी की जहां कार्य संस्कृति प्रभावित होती है, वहीं मानव संसाधन का भी ह्रास होता है। चूँकि संविधान के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारें अलग-अलग इकाइयां हैं। इस परिप्रेक्ष्य में संविधान में समानांतर किंतु भिन्न-भिन्न अनुच्छेद हैं। इनमें स्पष्ट उल्लेख है कि इनके चुनाव प्रत्येक पांच वर्ष के भीतर होने चाहिए। लोकसभा या विधानसभा जिस दिन से गठित होती है, उसी दिन से पांच साल के कार्यकाल की गिनती शुरू हो जाती है। इस लिहाज से संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि एक साथ चुनाव के लिए कम से कम 18 अनुच्छेदों में संशोधन किया जाना जरूरी होगा। विधि आयोग, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग और संविधान समीक्षा आयोग तक इस मुद्दे के पक्ष में अपनी राय दे चुके हैं। ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। यदि विपक्षी दल सहमत हो जाते हैं तो दो तिहाई बहुमत से होने वाले ये संशोधन कठिन कार्य नहीं हैं। 2024 में मोदी सरकार की बहाली हो गई है, इससे एक साथ चुनाव की उम्मीद बढ़ गई है। इस दौरान ईवीएम समेत अन्य चुनावी उपकरणों की जरूरत पूरी कर ली जाएगी। अनेक

शिविर में 120 बच्चों की हुई हीमोग्लोबिन जांच



मासिक धर्म स्वच्छता की जानकारी दे दी। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की काउंसलर श्रीमती राधा मिगलानी ने वीकली आयरन फोलिक एसिड प्रोग्राम

अभियान के नीरज बघेल ने बच्चों को टीवी जागरूकता कार्यक्रम के बारे में जागरूक किया एवं उनकी टीवी हेतु स्क्रीनिंग भी की गई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय

किया गया। टीम द्वारा अत्यधिक एनीमिक पाए गए बच्चों को उच्च चिकित्सा इकाइयों हेतु संदर्भित किया गया। कार्यक्रम में राजकीय इंटर कॉलेज जयनगर प्रभारी प्रध

के बारे में जागरूक किया और समस्त बच्चों से आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट को नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह खाने को कहा। टीबी मुक्त भारत

बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के फार्मासिस्ट के एन जोशी एवं स्टाफ नर्स सोनिया वैद्य द्वारा बच्चों के हीमोग्लोबिन की जांच की गई एवं आवश्यकता अनुसार दावों का वितरण

। नाचार्य बी एन गोस्वामी, कुमुद पाठक, दिलीप वैश्य एवं समस्त स्टाफ द्वारा सहयोग किया। कार्यक्रम के अंतर्गत 120 बच्चों के हीमोग्लोबिन की जांच की गई।

बीमारियों का भूत भगाओ
स्वच्छता का, मंत्र अपनाओ
स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत
जनहित में जाओ

हिन्दी साप्ताहिक उत्तरांचल दर्पण

Follows us: UttaranchalDarpan.in

Follows us: DarpanNews.net

FOLLOWS US: DARPAN NEWS

Watch us: DARPAN NEWS

'दंगापरस्तों' पर धामी सरकार का 'डबल अटैक'

-अर्श-

देहरादून। छोटी-छोटी घटनाओं पर देवभूमि की शांत वादियों में अराजकता, हिंसा एवं दंगा फैलाने के आदी दंगा परस्तों पर नकेल डालने के लिए उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पूरी तरह कमर कस ली है और अब सरकार दंगा परसंदगी पर डबल अटैक करने की तैयारी में है। उत्तराखंड सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के चलते एक ओर जहां बीते रोज उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है, वहीं दूसरी ओर राज्य शासन ने बाहर से आकर उत्तराखंड में शरण लेने वाले उपद्रवियों एवं अपराधियों को अपने रडार पर लेने के लिए एक बेहद सख्त सत्यापन प्रक्रिया की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। उत्तराखंड

उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक के कानून बनने के बाद अब बेहद सख्त सत्यापन अभियान छेड़ने की तैयारी, सत्यापन अभियान को प्रदेश के पर्वतीय जिलों में भी दिया जाएगा विस्तार, बोले सीएम धामी डेमोग्राफिक बदलाव की वजह से राज्य के मूल स्वरूप और संस्कृति को हरगिज नहीं होने दिया जाएगा प्रभावित

लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक के कानून बनने के बाद जहां हड़ताल, दंगों, बंद और आंदोलनों में सरकारी के साथ-साथ निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से क्षति वसूली की जा सकेगी, साथ ही नई सत्यापन प्रक्रिया के तहत बाहर से आकर देवभूमि में छिपे बैठे अराजक तत्वों की पहचान भी बेहद आसानी से की जा सकेगी। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में पहले से कहीं अधिक सख्त सत्यापन अभियान चलाए जाने के संकेत देते हुए कहा है कि उत्तराखंड में अब पहले से ज्यादा सख्ती से सत्यापन अभियान चलाया जाएगा और



इस अभियान के दायरे में अब पर्वतीय जिलों को भी लाया जाएगा। सीएम धामी ने कड़े शब्दों में कहा है कि उत्तराखंड के डेमोग्राफिक बदलाव की वजह से राज्य के मूल स्वरूप और संस्कृति को हरगिज प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सरकार इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि राज्य के मूल स्वरूप से किसी भी कोमत पर छेड़छाड़ न होने पाए। मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य के मूल स्वरूप की रक्षा के लिए सत्यापन अभियान चलाया गया था, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। अब इस सत्यापन अभियान को और

भी विस्तृत एवं सख्त बनाया जाएगा। सत्यापन अभियान को डेमोग्राफिक बदलाव वाले क्षेत्र में खास तौर से फोकस किया जाएगा। सीएम धामी ने राज्य से के बाहर से आकर देवभूमि में अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि उत्तराखंड एक सौहार्दपूर्ण राज्य है और यहां लोग प्रेमपूर्वक रहते हैं, लेकिन यहां की बहन-बेटियों के खिलाफ अपराध कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने अपराधियों को चेतावनी दी कि प्रदेश में अपराध करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है और अपराधियों के खिलाफ सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी संगीन एवं अशांति फैलाने वाले अपराध की स्थिति में सरकार सख्त से सख्त कदम उठाने में भी बिल्कुल नहीं हिचकेंगी।

विधेयक को राजभवन से मिली मंजूरी, उपद्रवियों पर कसेगा शिकंजा

देहरादून। उत्तराखंड में साम्प्रदायिक दंगा-फसाद करने वाले उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश सरकार ने अध्यादेश के तौर पर लागू इस कानून के लिए विधेयक पेश किया था। विधायी ने राज्यपाल की मंजूरी के लिए विधेयक को राजभवन भेजा था। इस कानून के तहत हड़ताल, दंगों, बंद और आंदोलनों में सरकारी के साथ-साथ निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली की जाएगी। इसके संबंध में एक दावा अभिकरण का गठन किया जाएगा। इसमें कोई भी व्यक्ति और सरकारी संपत्तियों का प्राधिकारी इस दावा अभिकरण में अपना दावा पेश कर सकेगा। इस दावे का निपटारा भी निश्चित समय अवधि में होगा, ताकि जल्द से जल्द नुकसान की भरपाई नुकसान करने वाले से हो सके। यदि किसी आंदोलन, बंद आदि में संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है तो इसकी भरपाई संबंधित बंद या आंदोलन का आह्वान करने वाले नेता से की जाएगी। क्षतिग्रस्त संपत्ति की भरपाई के अलावा आठ लाख तक का जुर्माना और दंगा नियंत्रण पर सरकारी अमले का खर्चा भी भरेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) विधेयक को मंजूरी देने पर राज्यपाल का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। इस कानून के तहत दंगाइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। दंगा नियंत्रण में लगे सरकारी अमले और अन्य कार्य पर आने वाले खर्च की भरपाई भी उपद्रवी से की जा सकेगी। देवभूमि में कानून व्यवस्था और स्वरूप बिगाड़ने की किसी को छूट नहीं है। इस कानून का राज्य में कड़ाई से पालन कराया जाएगा।



रेल पटरी के बीचों बीच बिजली का पोल रखने मचा हड़कंप

रुद्रपुर/ रामपुर(उद संवाददाता)। देश के कई राज्यों में रेलवे लाईन पर लोहे के रॉड व अन्य वस्तुओं के जरिये रेलगाड़ियों को डिरेल करने की की घटनायें लगातार बढ़ रही हैं। वहीं अब उत्तराखंड में भी ऐसी ही एक घटना से रेलवे की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। रेलवे लाइन पर किसी शरारती तत्वों द्वारा लोहे का खंभा रखे जाने पर खलबली मच गई। काठगोदाम-देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन के लोको पायलट ने रेलवे लाइन से खंभा हटाकर ट्रेन को गुजर गया। वहीं ट्रेन 20 मिनट लेट होकर रुद्रपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। उधर पुलिस अधीक्षक तथा जीआरपी पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर जायजा लिया। रुद्रपुर बॉर्डर से सिटी क्षेत्र की बलवंत एनक्लेव कालोनी के पीछे रेलवे लाइन पर खंभा संख्या 45/10 तथा 11 के बीच लोहे का भारी भरकम बिजली का पोल रखे होने पर बुधवार की रात खलबली मच गई। इस दौरान रुद्र

काठगोदाम-देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन के लोको पायलट की सूजबूझ से टला बड़ा हादसा, शरारती तत्वों की तलाश जारी



बिलास चौकी प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी रुद्रपुर रेलवे स्टेशन से मिलने वह मौके

पहुंच गए। बताया कि काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12091 देहरादून से वापस काठगोदाम जा रही

थी। इसी बीच ट्रेन के लोको पायलट ने रेलवे लाइन पर बिजली का खंभा देख तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रेल

को बेपटरी होने से बचा लिया। पटरी के बीचों बीच बिजली का खंभा रखे होने की सूचना से रेलवे भिाग के अधिकारियों में खलबली मच गई। इस दौरान ट्रेन के लोको पायलट ने ट्रेन को रोककर खंभे को रेलवे लाइन से हटकर ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया। बताया जाता है कि रात्रि 9:45 पर एक्सप्रेस ट्रेन को रुद्रपुर रेलवे स्टेशन पहुंचना था। जबकि वह 10 मिनट देरी से चल रही थी। ट्रेन 10:15 पर रेलवे स्टेशन रुद्रपुर उत्तराखंड पहुंची। तब जाकर ट्रेन के लोको पायलट ने स्टेशन अधीक्षक तथा जीआरपी पुलिस को आमले से अवगत कराने पर रेल कर्मियों तथा जीआरपी पुलिस में खलबली मच गई। सूचना पर स्थानीय पुलिस तथा जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंच गई। साथ ही सीओ रवि खोखर, प्रभारी

निरीक्षक बलवान सिंह पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधीक्षक विद्या किशोर मिश्र ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया कि वह ऐसे शरारती तत्वों पर नजर रखें और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उधर सूचना पर जीआरपी पुलिस अधीक्षक ने भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और जीआरपी पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं रेलवे के सुरक्षा अधिकारियों ने पटरी के बीचों बीच रखे गये बिजली के पोल रखने की घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि शरारती तत्वों द्वारा ऐसी हरकत को अंजाम दिया गया है। संदिग्धों की धड़पकड़ के साथ ही बिजली का खंभा छोड़ने की विस्तृत जांच की जा रही है। वहीं रेलगाड़ी को डीरेल करने के पीछे किसी बड़ी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जीआरपी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

गुरुजी उत्तराखंड की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल चेन

गर्मियों में ठंड जैसी राहत

गुरुजी

36 महीने तक की EMI उपलब्ध

Budget Ac

Premium Split Ac

Mid-Range Split Ac

Heavy-Duty Split Ac

SONY Whirlpool SAMSUNG ITB Haier BOSCH VOLTAS

DAIKIN HITACHI MITSUBISHI ELECTRIC GENERAL LLOYD BLUE STAR

Refrigerator की सबसे बड़ी रेंज उपलब्ध

Deep Freezer की सबसे बड़ी रेंज उपलब्ध

RO Purifier की सबसे बड़ी रेंज उपलब्ध

Water Dispencer की सबसे बड़ी रेंज उपलब्ध

Air Cooler की सबसे बड़ी रेंज उपलब्ध

Easy EMI Options Available

RUDRAPUR- Civil Line +91-9927882338, Kashipur Bypass +91-9690282777, Kashipur Bypass +91-9756233166, Sony Center +91-9917170230 KASHIPUR- Ramnagar Road +91 8791989500, Cheema Chauraha +91 9927813555 HALDWANI- Tikonia +91-9997207007, Pilikothi +91-8923468434, Pilikothi +91-9690256666, HARIDWAR- Haridwar +91-9761699704 MORADABAD- Moradabad +91-7500839146, GADARPUR- Near Super Market +91-9927850999, KICHHA- Kichha +91-7017595920, LOHAGHAT- Daak Bangla Road +91-9568035735 DEHRADUN- Kaluagarh Road +91-8394949454 PANIPAT- West Market Opp. Central Bank +91-8607964000 KARNAL- Mangal Singh Market +91-8684077000, 49 Ram Nagar +91-8908350000